feel that he would probably do well there. Otherwise, the first thing you will want to do in this House is to pass a vote of censure against me and run me out because I have never had any experience before of putting forward a Budget. The whole point is whether this man is fit or not. Simply because his experience was in another field, it does not mean that he has not got the sense of management or he cannot pick it up in a little time. If there has been any defect in any particular case, then that has got to be certainly gone into and whether the man has had experience of kind 'A' or kind of 'B' does not matter. The whole question is whether he has managed it properly or not, that is reflected in the way he has managed it,—and that should be enquired into. There are bodies which do that. As the House knows, very recently my good predecessor had set up a body to go into this very matter, *i.e.*, the Bureau of Public Enterprises. The body has been set up. It is going into action an it is trying to see where the defects lie. The really belongs to my friend.

Having done that, I finish here.

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1966

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI SACHINDRA CHAUDHURI): Sir, I move :

> "That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a par of the financial year 1966-67, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री के० सी० बघेल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया। मैं बजट पर बहुत देर से बोलने के लिए बैठा हुआ था लेकिन मुझे उस पर बोलने का अवसर ही नहीं मिल सका और अब जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बजट के संबंध में जो स्पीच हुई है उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी न करके, थोड़ा-सा समय जो मुझे मिला है उसमें चंद बातें शासन के विचारार्थ कहूंगा। मैं ये बातें इस ख्याल से रखना चाहता हूं कि आगे चलकर इस सूचना से सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करेगी और अगर उसमें कुछ रद्दोबदल या तबदीली करना चाहेगी तो अवश्य करेगी।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं और यह स्थान एक राइस प्रोड्यूसिंग एरिया कहलाता है और वह चावल का भंडार समझा जाता है। इस वक्त हमारे यहां मध्य प्रदेश में न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि विन्ध्य प्रदेश में भी अन्न की बड़ी भारी कमी है और वहां पर इस समय अकाल की अवस्था है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। आप सब लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज देश में ज्यादा अन्न उपजाने की बात चली है और हमें ज्यादा अन्न उपजाना भी चाहिये। आजकल हम यह देख रहे हैं कि देहातों में जो किसान हैं उनका ध्यान भी ट्रैक्टर और मैकेनाइज्ड फार्म की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसके अलावा हमने यह देखा है कि पहले हमारे यहां जो रशियन ट्रैक्टर डी० टी० 14 और एच० पी० 28 मिलते थे वे अब मिलने बंद हो गये हैं और बड़ौदा में एक फैक्टरी 'ट्रैक्टर एन्ड बुलडोजर प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से खुली है जिसने सरकार से कहा है कि वह रशियन ट्रैक्टर का इम्पोर्ट बंद कर दे ताकि यहां के ट्रैक्टरों को लोग ले सकें। स्वदेशी की भावना कौन नहीं पसंद करेगा, परन्तु आज जबकि बड़ौदा फैक्टरी वालों का निर्माण कार्य धीमी और असंतोषजनक हालत में है, जब वह हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सक रहा है, तब रशियन ट्रैक्टरों का इम्पोर्ट बंद करना 'ग्रो मोर फूड' की दृष्टि से घातक नीति होगी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस नीति को

[श्री के० सी बघेल]

वजह से हमारे किमानों के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि वे लोग 45 और 50 एच०पी० के ट्रैक्टरों को बहुत पसन्द करते थे और उन्होंने अपने फार्मों में और खेतों में इस ट्रैक्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि आजकल इन ट्रैक्टरों का अभाव है जिससे किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो रशियन ट्रैक्टर "बिला रस" नाम का है उसकी कीमत तो 11 हजार रुपया है और हिन्दुस्तान में जो ट्रैक्टर बनता है, जो 50 एच०पी० का है, उसकी कीमत 22,000 रुपया है। तो ये सब चीजें हो रही हैं और मैं गवर्नमेंट से आप की मार्फत यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब तक हमारी यह बड़ौदा में ट्रैक्टरों की फैक्टरी मुकम्मिल न बन जाय और जब तक वह पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए ट्रैक्टर पैदा न कर सकें तब तक वह जो किसानों के लिए हमारे यहां रशिया से ट्रैक्टर आते थे, उनको बन्द न किया जाय। आप के मार्फत मैं गवर्नमेंट की नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि हमारे सामने चम्बल की जमीन को रीक्लेम करने की समस्या है। असल में हम किसानों को वहां बसाना चाहते हैं। वहां विस्थापितों की भी समस्या है। वहां डाकुओं की भी समस्या है। लेकिन वहां लेवलिंग किये बगैर यह सब नहीं हो सकता। इसलिए यह ट्रैक्टरों की बात मैं आपकी नोटिस में लाया।

मैं अब दूसरा प्वाइन्ट जो बतलाना चाहता हूं वह है "फिफ्थ स्टील प्लान्ट"। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश का जो दावा था वह बलाडीला के लिए था। वह दावा जिस सूरत में कैंसिल किया जा रहा है या उसको जान-बूझ कर दुर्लक्ष किया जा रहा है, वह हालत बड़ी दर्दनाक है और उसकी ओर मैं आपके जरिये शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वह उस पर गंभीरता से विचार करे। हमारे मध्य प्रदेश के प्रति बहुत अन्याय किया जा रहा है यह कह कर कि विशाखापटनम ज्यादा उपयुक्त है और बैलाडीला उतना उपयुक्त नहीं है। मैं यह कहता हूं कि इस मामले में जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय का प्रधान कारण ऐंगलो अमेरीकन कंसोर्टियम का आना और उनका रिपोर्ट देना है। लेकिन इसमें एक बड़ी चिंताजनक बात जो है वह यह है कि ऐंगलो अमेरिकन कंसोर्टियम जो यहां पर आया उसके सामने मध्य प्रदेश के वह आफिसर्स हाजिर नही हो सके जो उससे पूरी जानकारी रखते थे। उनका एक ज्वाइन्ट टूर होने वाला था और उस ज्वाइन्ट टूर की जो डेट थी वह 14-3-65 की तय की गई थी। हमको नहीं मालूम है कि किन कारणों से उन्होंने उस डेट को और उस प्रोग्राम को कायम रखना उचित नहीं समझा। उसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को जो सलाह मशविरा और जो बातें ठीक-ठीक बताई जाती, उनको वे नहीं बताई जा सकीं और उसका भयंकर परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनमाने ढंग से जो चाहा वह लिखा और हमारा केस फेल हो गया। हम उसकी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते है। मैं निश्चित दावे से कहना चाहता हूं कि जो विशाखापटनम है उसके मुकाबिले में बैलाडीला की कहीं ज्यादा अच्छी साइट है। उसके कारणों को बताते हुये मैं जल्दी-जल्दी कुछ प्वाइन्ट्स आपके सामने बता देता हूं। चाहे उसको आप साइट सिलेक्शन की दृष्टि से देखिये, चाहे आयरन ओर की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे लाइम स्टोन की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे डोलोमाइट की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे क्वार्टजीन की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे बाक्साइट की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे मैंगनीज की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे कोल की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखिये, चाहे वाटर सप्लाई की दृष्टि से देखिये, चाहे डीप वाटर साइट के प्रश्न को एक्जामिन कीजिये, आपको मालूम होगा कि हमारे यहां जो बैलाडीला की साइट है वह कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और

हमारे यहां यह जो फिफ्थ स्टील प्लान्ट की चर्चा चली है, उसके लिए वह ज्यादा अधिकारी है । मैं उसके साइट सिलेक्शन के बारे में यह बतला दूं कि बैलाडीला के निरीक्षण का केवल नाटक किया गया है । कंसोर्टियम वालों ने हमारे यहां के आफिसर्स से ठीक-ठीक बात नहीं की और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने ग़लत, इनएकूरेट और इरोनियस रिपोर्ट पेश की । हमारे यहां मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि जो स्टील प्लान्ट हो वह चितलंका ग्राम में लगाया जाय । लेकिन बजाय चितलंका गांव जाने के कंसोर्टियम ने मुस्तलनगर और भुंडरी गांवों की जांच की और वहां की जांच करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी । चितलंका गांव जो है वह डांकिनी और शंखिनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है । उसके पास ही सप्तगंधा नदी बहती है । किसी भी स्टील प्लांट के लिए इससे बढ़िया पानी का स्थान और क्या हो सकता था ? और वहां की स्वायल जो है वह मूरम स्वायल है, वहां नेचुरल ड्रेनेज है, वहां पर स्पार्स पापुलेशन, विरली आबादी है और कल्टीवेशन के लिये वहां पर काफी गुंजाइश है । विशाखापटनम में इसके मुकाबिले में ऐसी कोई सुविधा नहीं है । वहां वाटर टेबुल ग्राउण्ड लेवल से 2 मीटर ऊंचाई पर है, Sub-soil information is not adequate, यह अपनी रिपोर्ट में कंसोर्टियम ने कहा है । इस तरह साइट सिलेक्शन में भारी पक्षपात हुआ है । आयरन ओर की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से चितलंका की दूरी माइन्स से 30 किलोमीटर है । अब मैं आयरन ओर की अवेलेबिलिटी के बारे में और अधिक डिटेल में न जाकर के यह कह देना चाहता हूं कि एक प्लान्ट के लिये जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, विशाखापटनम के मुकाबिले में बैलाडीला बैटर पोजीशन में है । इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने डिटेल में बताया है और मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि वह गहराई से इसकी जांच करे ।

अब मैं भिलाई स्टील प्लान्ट के मैनेजमैंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो आज एक बड़ी भारी प्राब्लम हो रही है । मैं आपकी मार्फत शासन को यह बतला देना चाहता हूं कि मुझे भय है कि कुछ दिनों बाद कहीं वैसी ही स्थिति वहां न पैदा हो जाये जैसी बिहार और बंगाल में पैदा हुई । मैं शासन को यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर योग्य और शिक्षा प्राप्त स्थानीय लोगों की अवहेलना हो रही है और उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है । हमारे यहां राजे-महाराजे तो खत्म हो गये, लेकिन जमींदारी एबालीशन के बाद में ये जो बड़े-बड़े पब्लिक सेक्टर में कारखाने खुले, उनमें नये-नये राजे महाराजे बना दिये गये । वे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को बना सकते है, बिगाड़ सकते हैं और तमाम किस्म की बातें कर सकते हैं । मैं आपकी मार्फत शासन की नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि रांची में जो हैवी मशीनरी का प्लान्ट है वहां पर 1964 की जनवरी में एक बड़ा भारी झगड़ा हुआ था । उस पर जस्टिस बी० मुकर्जी की रिपोर्ट है जो उन्होंने गवर्नमेंट को पेश की थी । उसमें उन्होंने सिफारिश की है कि एक आदमी के ऊपर तमाम बातें नहीं छोड़नी चाहियें । पालिसी मैटर भले ही वह डिसाइड करे । मैंने वह रिपोर्ट ले कर के अपने पास रखी थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिये मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा । मैं आपकी मार्फत यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट के मुताबिक अमल किया जाय ताकि एक ऐसा सर्विस कमिशन नियुक्त हो जो तमाम बातों को जांचे, देखे कि किसको नौकरी देनी है, किसको नौकरी नहीं देनी है और किसको क्या करना है । यदि इस पर जल्दी अमल नहीं किया गया तो हो सकता है कि वहां भी दूसरे स्थानों की तरह विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाय । छत्तीसगढ़ के लोग स्वभाव से झगड़ा करने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ, तो बाद में उन पर काबू पाना कठिन हो जायगा ।

[श्री के० सी० बघेल]

अब मैं दो तीन मिनट में कुछ थोड़ी सी बातें और आपके सामने रख देना चाहता हूं। एक तो यह है कि एक फर्टिलाइजर प्लान्ट कोरबा में हो। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में बताया था कि दुर्गापुर और कोचीन, इन दो जगहों पर फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाये जायेंगे। मैं उनसे सिफारिश करूंगा कि वे कोरबा के केस को भी एक्जामिन करें क्योंकि कोरबा एक ऐसे स्थान पर है जहां पानी की बड़ी सहूलियत है। सरकार ने उसके लिये एक करोड़ रुपया पहले से मंजूर कर दिया था। उसकी साइट को सिलेक्ट कर लिया गया था, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बन गई थीं और इतना सब होने के बाद सरकार कहती है कि वहां फर्टिलाइजर महंगा पड़ेगा क्योंकि अब कोल गैस और नेप्था का सवाल उठाया गया है कि कोल गैस से नेप्था सस्ता होगा और कोल वहां लाखों टन उपलब्ध है और नेप्था की हालत अनिश्चयात्मक है। केन्द्रीय रसायन मंत्रालय को अभी तक यह पता नहीं है कि कितनी नेप्था की जरूरत पड़ेगी और उसे पूरा कर सकेंगे या नहीं। कोल गैस जब हमारे पास है ही, तो ऐसी हालत में संकटकालीन अवस्था को देखते हुये इस पर शीघ्रता से विचार किया जाय।

इसके साथ-साथ कोरबा में एक कागज का कारखाना पब्लिक सेक्टर में होना जरूरी है। हमारे यहां बांस बहुतायत से होता है। इसलिये वहां पर जल्दी से जल्दी एक कागज का कारखाना हो।

यह भी मैं बताना चाहता हूं कि इरीगेशन के लिये हसदेव नदी पर एक बांध बनाया जाय। मैं शासन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि बिलासपुर में एक मेडिकल कालेज की सख्त जरूरत है। मेडिकल कौंसिल ने भी यह कहा है कि 50 लाख की पापुलेशन वाले स्थान पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिये और बिलासपुर कमिश्नरी की पापुलेशन करीब-करीब 50 लाख है, इसलिये वहां पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिये।

मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन चूंकि समय नहीं है, इसलिये मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

PROF. M. B. LAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I heard very patiently the learned discourse delivered to us by the Finance Minister. It is not possible for me just at this time to deal with all the points to which the Finance Minister was good enough to invite our attention. But I do feel that it would be proper for us to take into consideration some of those points.

As the House knows, I am more interested in socialism than in many other qhestions pertaining to the economic affairs of this country.

SHRI M. SATYANARAYANA (Nominated): Not as a way of life.

PROF. M. B. LAL: Sir, socialism undoubtedly is a way of life and unless it is realised in life, mere structural changes will not be sufficient. But socialism does require a structural change and the problem of socialism is also a structural problem as I pointed out in my speech. I would have been very glad if the Finance Minister had been good enough either to say that his Government does not stand for socialism or would have pointed out to us in what way the structural change is being brought about by our Government.

Sir, I beg to submit that no efforts are being made even now to bring about a change in our way of life. Not to speak of socialism, even a democratic way of life is not being brought about by this Government. I feel, Sir, that even to bring about a socialist way of life, the reimposition of Expenditure Tax is very necessary. I do not conceive of the Expenditure Tax as an alternative to high Income-tax. To me, the imposition of the Expenditure Tax is necessary to force the rich to lead a simple life, not to waste the resources of the country which can be better utilised for the purpose of production. The Finance Minister said that even when in India we have high

taxation there are persons who keep with them after the payment of taxes three or four lakhs per year. I wish the Expenditure Tax to be imposed upon them so that those three or four lakhs of rupees may not be utilised ostentatiously in any wasteful expenditure.

So far as the sugar policy is concerned, the less said the better. I think the Government could not bungle the affairs more than it has done in the case of sugar. We know that there is sugar in the godowns, we know that the sugar-cane growers are not being paid. We feel now that there is need for decontrol, that there is need for people to have more sugar at a reasonable rate. And yet we are imposing a tax on sugar. Attention is invited to the difference in the sugar policy and the gur policy. The Finance Minister is just new to the office, perhaps to this Parliament also, and therefore he does not know that this difference led the Government to impose such restrictions on the manufacture of gur and on the export of gur from one State to the other State that many people including myself had to be the guests of His Majesty's Guest House for some time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): There is no His Majesty in India now.

PROF. M. B. LAL: Very well, the Government's Guest House, if you like a jail to be so called.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Chaudhuri has been in Parliament quite long.

PROF. M. B. LAL: Yes, but I am sorry that he did not take note of the fact that many of us in this House as well as in the other House had to court arrest as a protest against that policy.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): There are many majesties here now; there was one Majesty before.

PROF. M. B. Lal: The Finance Minister pointed out that he is an amateur and yet he is ready to be the Finance Minister. I beg to submit that, once, in Great Britain, a person was appointed as the Chancellor of the Exchequer who, when the budget was presented before him, said, "What do these damned dots mean ?" That is to say, he was not able to understand the significance of decimal dots. But if we are going to have some such persons as managers or directors of the public undertakings, God help our public undertakings.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): He did not mean that. He meant. . .

PROF. M. B. LAL: I beg to submit that in a parliamentary democracy some amateurs who may be conversant with the public opinion of the country, who may be conversant with the public policy of the party in power, may be appointed as Finance Ministers. They may be able to project that public policy with the help of experts and may become successful Finance Ministers, though many have failed to be so. Public undertakings cannot be run by such amateurs. I beg to submit that unless we try to organise an Economic Civil Service and entrust the administration and management of public undertaking to persons qualified in the management of those undertakings, it will not help us. Prof. Mukut Behari Lal may be a good professor but he is incompetent to manage a public undertaking, though, when his party happens to be in power, he may be vested with some ministerial post.

The Finance Minister invited our attention to certain saying of a great Indian administrator, Bhishma. I beg to submit that we are neither Bhishmas nor Manus but socialists. And when we talk of forming a social society, with due respect to those great Leaders, we will have to admit that they cannot be any guide to us. Further, I request the Finance Minister to read Bhishma's 'Tenets of Fiscal Policy'. He will find that his financial policy does not conform even to the principles laid down by Bhishma.

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : उपसभापति जी, हमारे मध्य प्रदेश के सदस्य ने कुछ बातें उठाईं। उन्होंने लोहा और स्टील प्लांट की साइट

[श्री ललित नारायण मिश्र]

के बारे में चर्चा की । रांची हैवी इंजीनियरिंग, कोरबा और नेप्था के विषय में भी चर्चा की । जो मिनिस्ट्री सम्बन्धित हैं उनके पास उनके भाषण जायेंगे और जो बातें वे मालूम करके बता सकेंगे बतायेंगे ।

अभी हमारे प्रोफेसर साहब, मुकुट बिहारी लाल जी, जिन्हें मैं बहुत दिनों से जानता हूं—चाहे उन्हे पता हो या न हो—तब से जानता हूं जब वे बनारस में थे और मैं वहां विद्यार्थी था, अभी उनके और हमारे मंत्री जी के बीच बातें हुई । समाजवाद क्या है . . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Was he your student?

SHRI L. N. MISHRA: Yes.

समाजवाद की बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया उनके साथ यह अन्याय होगा और समस्त सदन के साथ अन्याय होगा अगर में उसके बारे में प्रोफेसर साहब यह समझें कि वह एक एमेच्योर फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण था ।

मेरे ख्याल से यह एक ऊंचे दर्जे का भाषण था । . . .

PROF. M. B. LAL: He himself said that he was an amateur.

श्री ललित नारायण मिश्र : . . . और शायद उनका जो भी काम चल रहा है, जिस तरह से वह चला रहे है बहुत ही व्यावहारिक और एक ऊंचे दर्जे का है, जैसा भी मंत्री को होना चाहिये वैसी बड़ी कुशलता के साथ चला रहे हैं ।

अब, जहां तक समाजवाद को छोड़ने की बात है तो जब तक कांग्रेस सत्ता में है यह असंभव बात है, हम समाजवाद नहीं छोड़ सकते हैं, हम उनके साथ हैं, हम स्ट्रक्चरल चेंजेज में विश्वास करते हैं और हम भी समझते हैं कि हिन्दुस्तान का कल्याण तभी हो सकता है जब कि समाजवाद पूरे रूप में आये, जो सरकार इससे हटेगी वह सत्ता में नहीं रह सकती । कांग्रेस एक जीवित संस्था है और उस संस्था की यह सरकार है और इस संस्था के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल जी थे और वह इसको लाये । तो हम समाजवाद को लाना चाहते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि चर्चा करने से कहां तक समाजवाद आ सकता है, और शासन चलाने के साथ-साथ कहां तक कैसे समाजवाद आ सकता है, फर्क इतना है कि विरोधी सीट मे बैठ कर समाजवाद की चर्चा करने मे और सत्तारूढ़ हो कर समाजवाद की चर्चा करने में, कुछ फर्क हो जाता है लेकिन सोचने में कोई फर्क की बात नही है, जितनी उनकी ख्वाहिश है हिन्दुस्तान के गरीबों के बारे में, हिन्दुस्तान के मजदूरों के बारे में, उससे कम, किसी से कम, हम लोगों में नही है । हम भी चाहते है कि समाजवाद आये, हमारी संस्था चाहती है कि समाजवाद आये । हमारा लक्ष्य है समाजवाद, वे उनकी बगल में जो सदस्य है वह समाजवाद नही चाहते हैं, बहुत से विरोधी दल के सदस्य समाजवाद नहीं चाहते है, हम लोगों की एक बात है, हम समाजवाद चाहते है । तो यह आक्षेप न करें, यह कोई न्याय की बात नही होती है ।

मै ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, इतना ही कहूंगा कि मध्य प्रदेश के हमारे सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उनको हम सम्बन्धित मंत्रालयों में भिजवा देंगे और मैं प्रोफेसर साहब से कहूंगा कि सरकार को जिस चश्मे से देखते हैं उसका रंग बदल कर देखने की कोशिश करें, चूंकि वह एक ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से देखने की कोशिश करें, यह हमारी अपेक्षा है ।

SHRI P. N. SAPRU: It is very well known that democracy is governed by the amateur plus the experts. Therefore, I do not understand how my friend interpreted those words in a different way.

PROF. M. B. LAL: I had nothing personal in mind.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I am glad you made it clear that our Finance Minister is not an amateur in the sense in which generally it is taken to be.

The question is :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1966-67, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were aded to the Biil.

SHRI L. N. MISHRA : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-five minutes past four of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 24th of March, 1966.

L35RS/66—574—7-2-67—GIPF.